

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उ०प्र०।
- 2-समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,  
उ०प्र०।

पत्रांक : राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/8365 लखनऊ/दिनांक 18-03-2020  
विषय : प्रदेश में कोरोना वाइरस संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान-मसाला एवं तम्बाकू उपभोग को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश-786/तीन-18-06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

उक्त के क्रम में जैसा कि आप अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा-निर्देश एवं हेल्पलाइन नम्बर- 18001805145 जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

आपके संज्ञान में लाना है कि GATS सर्वे-2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में धूम्रपान करने का प्रतिशत 13 प्रतिशत है, जो कि GATS सर्वे-2009-10 की रिपोर्ट की तुलना में घटा है, जबकि धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करने वालों का 29.4 प्रतिशत है, जो कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में 4 प्रतिशत बढ़ा है।

चूंकि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बहुउद्देश्यीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल सी०ओ०टी०पी०ए०-2003 के नियमों/उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान-मसाला खाकर यत्र-तत्र थूकने पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/

लखनऊ/दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3-उप महाप्रबन्धक, एन०सी०डी०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4-समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उ०प्र०।
- 2-समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,  
उ०प्र०।

पत्रांक : राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/

लखनऊ/दिनांक 18-03-2020

विषय : प्रदेश में कोरोना वाइरस संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान-मसाला एवं तम्बाकू उपभोग को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश-786/तीन-18-06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

उक्त के क्रम में जैसा कि आप अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गम्भीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा-निर्देश एवं हेल्पलाइन नम्बर- 18001805145 जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

आपके संज्ञान में लाना है कि GATS सर्वे-2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में धूम्रपान करने का प्रतिशत 13 प्रतिशत है, जो कि GATS सर्वे-2009-10 की रिपोर्ट की तुलना में घटा है, जबकि धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करने वालों का 29.4 प्रतिशत है, जो कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में 4 प्रतिशत बढ़ा है।

चूंकि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बहुउद्देश्यीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल सी०ओ०टी०पी०ए०-2003 के नियमों/उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान-मसाला खाकर यत्र-तत्र थूकने पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/8366-69

लखनऊ/दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3-उप महाप्रबन्धक, एन०सी०डी०, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4-समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-5  
संख्या-548/पांच-5-2020  
लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2020

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य कोविड-19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है जो कि खतरनाक महामारी है और सम्प्रति प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त हैं;

अतएव महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं:

1. यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 कही जायेगी।
2. इस विनियमावली में महामारी का तात्पर्य कोविड-19 (कोरोना वायरस रोग, 2019) से है।
3. इस विनियमावली के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश, मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक, निदेशक, प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, जिलों के चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा प्राधिकृत अधिकारी होंगे।
4. समस्त चिकित्सालयों (सरकारी एवं निजी) में कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग के लिए आई0एल0आई0 या फ्लू कार्नर होना चाहिए।
5. चिकित्सालयों (सरकारी एवं निजी), सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के चिकित्सालयों और आयुष व्यवसायियों सहित रजिस्ट्रीकृत निजी चिकित्सा व्यवसायियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के सम्बन्ध में जिन्होंने उनकी जानकारी में विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोविड-19 से ग्रसित देशों की यात्रा की है और जिनमें बुखार या खांसी या श्वसन सम्बन्धी परेशानी या कोविड-19 के कोई चिन्ह और लक्षण न हों, सम्यक रूप से भरे हुए स्वघोषित प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित जिला निगरानी ईकाई को अधिसूचित करें। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के संदिग्ध या पुष्टिकृत मामलों के सम्पर्क में आने की इतिवृत्ति अभिलिखित की जायेगी और

एक-यदि गत 14 दिवसों में किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इतिवृत्ति हो और उक्त व्यक्ति अलक्षणीय हो तो उक्त व्यक्ति को अभिदर्शित होने के दिनांक से 14 दिनों के लिए गृहसंगरोधन में रखा जाना आवश्यक होगा।

दो-यदि गत 14 दिवसों में व्यक्ति की ऐसी कोई इतिवृत्ति हो और उक्त व्यक्ति कोविड-19 की रोग परिभाषा के अनुसार लक्षणीय हो तो उक्त व्यक्ति को प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सालय में पृथक रूप में रखा जाना आवश्यक होगा और प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 के लिए उसका परीक्षण किया जाएगा।

तीन-ऐसे मामलों की सूचना तत्काल जिला के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में दी जानी चाहिए।

6. कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की पूर्व अनुज्ञा विना कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना हेतु किसी मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। यह कोविड-19 के सम्बन्ध में किसी अफवाह या अप्रमाणिक सूचना के प्रसार के रोकने के लिए है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो इसे इस विनियमावली के अधीन दण्डनीय अपराध के रूप में माना जायेगा।
7. कोविड-19 हेतु परीक्षण सम्बन्धी नमूना लेने के लिए प्राधिकृत प्रयोगशालायें ही भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नमूना संग्रहीत करेंगी। ऐसे नमूने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत या नियत प्रयोगशालाओं में प्रेषित किए जायेंगे।
8. ऐसे किसी देश या क्षेत्र जहाँ से कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की गयी हो, में गत 14 दिवसों में यात्रा की इतिवृत्ति सहित किसी व्यक्ति को निकटतम सरकारी चिकित्सालय को सूचित करना या जिला नियंत्रण कक्षों की शुल्क मुक्त हेल्पलाइन संख्या-1800-180-5145/0522-2230006/0522-2230009/0522-2616482 पर काल करना आवश्यक होगा ताकि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक उपाय यदि अपेक्षित हों, किये जा सकें।
9. ऐसे किसी देश या क्षेत्र जहाँ से कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना गत 14 दिवसों में प्राप्त की गयी हो, में यात्रा की इतिवृत्ति वाले समस्त व्यक्तियों जिनमें खांसी, बुखार या श्वसन में कठिनाई का कोई लक्षण न हो, स्वयं को पृथक रखना चाहिए और मुख तथा नाक को मारक से ढकना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों से आगमन किये जाने के दिनांक से 14 दिवसों के लिए पारिवारिक सदस्यों सहित किसी व्यक्ति के सम्पर्क से बचने की सावधानी बरतनी आवश्यक है।
10. इस विनियमावली के प्रस्तर-3 के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र, जहाँ कोविड-19 महामारी हो, की यात्रा का इतिवृत्ति हो और सम्बन्धित व्यक्ति लाक्षणिक हो, को भर्ती करने और पृथक करने के लिए प्राधिकृत हैं।
11. यदि कोविड-19 के मामले का संदिग्ध व्यक्ति भर्ती या पृथककरण के लिए इन्कार करता है तो इस विनियमावली के प्रस्तर-3 में प्राधिकृत अधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि वह ऐसे मामले के व्यक्ति को लक्षणों के प्रकट होने के 14 दिवसों की अवधि के लिए अथवा प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने तक अथवा ऐसी आवश्यक अवधि तक के लिए बलपूर्वक भर्ती तथा पृथककृत करे।
12. यदि कोविड-19 के मामले के सम्बन्ध में सूचना, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यथा ग्राम, कस्बा, वार्ड, कालोनी, बस्ती से प्राप्त हो तो सम्बन्धित जिला के जिला प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह उक्त रोग के फैलाव को रोकने के क्रम में निम्नलिखित रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित करे किन्तु इन्हीं तक सीमित न रहे;  
एक-भौगोलिक क्षेत्र को सील किया जाना।  
दो- प्रभावित क्षेत्र से जनसंख्या के प्रवेश और निकास पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।  
तीन-विद्यालयों, कार्यालयों को बन्द किया जाना और सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबन्ध लगाया जाना।  
चार- क्षेत्र में वाहनों के संचलन को रोका जाना।

पांच-भारत सरकार के समुदाय आधारित संपर्क अनुसंधान क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार कोविड-19 के मामलों में सक्रिय और अक्रिय निगरानी प्रारम्भ करना।

छ:- समस्त संदिग्ध मामलों के व्यक्तियों को चिकित्सालय में पृथक करना।

सात-संदिग्ध मामलों के व्यक्तियों के पृथक्करण के लिए संरोधन इकाई के रूप में किसी सरकारी/निजी भवन को अधिभूत करना।

आठ-समस्त सरकारी विभागों के कर्मचारिवृन्द संरोधन उपायों के कर्तव्य निर्वहन के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के जिला प्रशासन के निवर्तन पर होंगे।

नौ- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा निर्देशित कोई अन्य उपाय।

13. जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला आपदा प्रबन्धन समिति अपने सम्बन्धित जिला में कोविड-19 हेतु संरोधन उपायों के सम्बन्ध में रणनीति का नियोजन करने के लिए प्राधिकृत हैं। जिला मजिस्ट्रेट इस विनियमावली के अधीन इस क्रियाकलाप के लिए जिला आपदा प्रबन्धन समिति हेतु विभिन्न विभागों से अधिकाधिक कार्मिकों को सहयोजित कर सकता है।
14. जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर ऐसे व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए, जिस हेतु उसे कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम करने के उद्देश्य से संगरोधित या पृथक्कृत किया गया हो, प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है और यह नियोजन कर्ता के लिए बाध्यकारी होगा कि वह पूर्ण परिलक्षियों सहित ऐसे प्रभावित व्यक्ति को विशेष अवकाश प्रदान करे।
15. शास्ति: इस विनियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-88 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को दण्डित कर सकता है, यदि वह इस विनियमावली के उपबन्धों या इस विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्हीं अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।
16. विनियमावली के अधीन कार्यरत व्यक्तियों का संरक्षण जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय इस विनियमावली के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।
17. यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 अप्रैल, 2020 या अग्रिम आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए विधिमान्य रहेगी।

*अमित मोहन प्रसाद*

(अमित मोहन प्रसाद)  
प्रमुख सचिव

**UTTAR PRADESH SHASAN  
CHIKITSA ANUBHAG-5**

IN pursuance of provisions of clause-(3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.548/five-5-2020 dated March, 2020.

**NOTIFICATION**

**No. 548/five-5-2020  
Dated Lucknow, 14 March, 2020.**

WHEREAS the State Government is satisfied that the state is threatened with an outbreak of Covid-19 disease which is dangerous epidemic disease and the ordinary provisions of law for the time being in force are insufficient for the purpose;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers under section-2 of the Epidemic Disease Act-1897 (Act no.3 of 1897) the Governor is pleased to make the following regulations: -

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 Regulations, 2020.
2. "Epidemic disease" in these regulations means COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).
3. Authorized persons under these regulations shall be the Director General, Medical & Health, Uttar Pradesh, Director General, Medical Education and Training, Uttar Pradesh, all Principals Government Medical Colleges, Uttar Pradesh, Superintendents of hospitals attached with medical colleges, Director/SIC/CMS of District-level hospitals, Chief Medical Officers, District Magistrates, Sub-District Magistrate, Medical Officers in the Districts and officers as authorized by the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh.
4. All hospitals (Government and Private) should have ILI or Flu corners for screening of suspected cases of COVID-19.
5. It shall be mandatory for hospitals (Government and Private), Medical Officers in Government health institutions and registered Private Medical Practitioners, including AYUSH practitioners, to notify such person(s) to concerned District Surveillance Unit along with duly filled up self declaration forms, who, within their knowledge, are having travel history of COVID-19 affected countries as per the extant guidelines and are having complaints of fever or cough or respiratory difficulty or even without any sign and symptoms of COVID-19. In


addition the history of coming in contact with suspected or confirmed cases of COVID-19 shall be recorded and

- i. In case the person has any such history in the last 14 days and the person is asymptomatic, then the person must be kept in home quarantine for 14 days from the date of exposure.
  - ii. In case the person has any such history in the last 14 days and the person is symptomatic as per case definition of COVID-19, the person must be isolated in the hospital as per protocol and will be tested for COVID-19 as per protocol.
  - iii. Information of such cases should be given to the office of CMO of the District immediately.
6. No person/institution/organization will use any print, electronic or social media for information regarding COVID-19 without prior permission of the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh. This is to avoid spread of any rumour or unauthenticated information regarding COVID-19. In case, any person/institution/organization is found indulging in such activity, it will be treated as punishable offence under these regulations.
  7. Only laboratories authorized to take test samples for COVID-19 will collect the samples as per guidelines of the Government of India. Such samples will be sent to laboratories, authorized or appointed by the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh.
  8. Any person with a history of travel in last 14 days to a country or area from where COVID-19 has been reported must report to nearest Government hospital or call a toll-free helpline numbers 1800-180-5145/0522-2230006/0522-2230009/0522-2616482. District Control rooms so that necessary measures if required may be initiated by the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh.
  9. All persons with a history of travel to a country or area from where COVID-19 has been reported in the last 14 days, but who do not have any symptoms of cough, fever, difficulty in breathing, should isolated themselves at home and cover their mouth and nose with a mask. Such persons must take precautions to avoid contact with any person including family members for 14 days from the date of arrival from such areas.
  10. Authorized persons as per para-3 of these regulations are authorized to admit a person and isolate the person if required in case he/she has a history of visit to a specified region where COVID-19 is endemic and the concerned person is symptomatic.
  11. If suspected case of COVID-19 refuses admission or isolation, the officer authorized in para-3 of these regulations will have power to

- forcefully admit and isolate such case for a period of 14 days from the onset of symptoms or till the report of lab tests are received or such period as may be necessary.
12. If the case of COVID-19 is reported from a defined geographical area such as village, town, ward, colony, settlement, the District Administration of the concerned district shall have the right to implement following containment measures, but not limited to these, in order to prevent spread of the disease.
- i. Sealing of the geographical area.
  - ii. Barring entry and exit of the population from the containment area.
  - iii. Closure of schools, offices and banning public gatherings.
  - iv. Banning vehicular movement in the area.
  - v. Initiating active and passive surveillance of COVID-19 cases, as per Community based Contact Tracing Implementation Guidelines of GOI.
  - vi. Hospital isolation of all suspected cases.
  - vii. Designating any Government/Private building as containment unit for isolation of the cases.
  - viii. Staff of all Government Departments will be at the disposal of district administration of the concerned area for discharging the duty of containment measures.
  - ix. Any other measures as directed by the Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh.
13. District Disaster Management Committee headed by District Magistrate is authorized for planning strategy regarding containment measures for COVID-19 in their respective Districts. The District Magistrate may co-opt more officers from different departments for the District Disaster Management Committee for this activity under these regulations.
14. District Magistrate may grant a certificate on the recommendation of Chief Medical Officer to the person for the period for which he was quarantined or isolated in order to prevent transmission of COVID-19 and it will be obligatory on the part of employer to grant special leave to such affected person with full emoluments.
15. **Penalty:** Any person/institution/organization found violating any provision of these regulations shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of Indian Penal Code (45 of 1860). Competent authority may penalize any person/institution/organization if found violating provisions of these regulations or any other further orders issued by Government under these regulations.



- 16. Protection of persons acting under the regulations:** No suit or legal proceedings shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith under these regulations unless proved otherwise.
17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 30<sup>th</sup> April, 2020 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

  
14-3-2020

( Amit Mohan Prasad )  
Principal Secretary